राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक प.7(37)गृह–12/कारा/2016 जयपुर, दिनांक : 18 SEP 2019

–: आदेश :–

राज्य की कारागृहों में संचालित उद्योगशालाओं के इन्फ्रास्ट्रक्चर (Machines & equipments, Manpower, Building etc.) के आधुनिकरण एवं बंदियों के पुर्नवास एवं कल्याण के प्रबंधन हेतु निम्नानुसार जेल विकास बोर्ड (Prison Dovelopment Board) का एतद् द्वारा गठन किया जाता है:–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय	चैयरमेन
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह	एक्स ऑफिसियो डाइरेक्टर
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त	एक्स ऑफिसियो डाइरेक्टर
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि	एक्स ऑफिसियो डाइरेक्टर
5. रजिस्ट्रार (प्रशासन) मान. राज. उच्च न्यायालय पीठ जयपुर	एक्स ऑफिसियो डाइरेक्टर
6. महानिदेशक कारागार	एक्स ऑफिसियो डाइरेक्टर
7. निदेशक, अभियोजन	एक्स ऑफिसियो डाइरेक्टर
8. श्री एस.एस. बिस्सा, सेवानिवृत आई.ए.एस.	गैर सरकारी सदस्य
9. श्रीमती गीता बरवड़, जोधपुर	गैर सरकारी सदस्य
10. उप निदेशक, उद्योग (जेल)	एक्स ऑफिसियो डाइरेक्टर
11. महानिरीक्षक कारागार	एक्स ऑफिसियो डाइरेक्टर
	मैनेजिंग डाइरेक्टर कम मेम्बर सेक्रेटरी

आज्ञा से,

(पी.सी. बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
7. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
9. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
11. उप निदेशक, उद्योग (जेल), राजस्थान, जयपुर।
12. श्री एस. एस. बिस्सा, सेवानिवृत आई.ए.एस. निवासी 117 पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर।
13. श्रीमती गीता बरवड़, निवासी 11, गॉधी कॉलोनी, भगत की कोठी, गंदे नाले के पास, पाली रोड़, जोधपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव

distinguished themselves in the field of prison administration or prison reforms or service to prisoners or human rights

(k) Inspector General of Prisons — Ex-officio Managing Director

32.21 The functions of the Board shall be:

(a) to examine the living conditions of prisoners in all the prisons, with specific reference to their basic needs and provision of facilities compatible with the dignity of human life.

(b) to build new prisons where the existing prisons are not in a satisfactory condition, or are beyond repairs.

(c) to review and suggest measures for the development of programmes for the 'treatment of prisoners, including research, education, vocational training and skill development, with a view to developing prisons as correctional centres.

(d) to efficiently manage prisons by inducting modern technology, methods and apparatus.

(e) to collaborate with corporate houses for Corporate Social Responsibility (CSR) funding for above purposes.

32.22 The Board shall have, and maintain, its own fund as the Prisons Development Fund to which shall be credited:

(a) all money received by the board from the State and Central Governments by way of grants, loans, advances, etc.

(b) all money borrowed by the Board by way of loans or debentures.

(c) all money generated by the agricultural, horticultural, industrial or manufacturing activities undertaken by prisoners.

(d) all fees, charges and profits received by the Board.

(e) all money received by the Board from the disposal of lands, buildings and other properties (movable or immovable), and

(f) all money received by the Board by way of rents or profits or in any other manner or from any other source.

32.23 The concerned State Government shall frame detailed rules for the functioning of the Board.

Publication of Annual Report

32.24 Each State shall publish an annual report on the functioning and progresses achieved by the Department of Prisons and Correctional Services and place the same before the legislature.